

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी- गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या- 02/2022

1. धर्मपाल पुत्र हरद्वारीलाल जाति जाट निवासी मोड़ा खेड़ा तहसील आदमपुर जिला हिसार हरियाणा।

- अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा

- असल रेस्पो.

2. नरेन्द्र पुत्र हरद्वारीलाल जाति जाट निवासी मोड़ा खेड़ा तहसील आदमपुर जिला हिसार हरियाणा।

-तरतीबी रेस्पोडेन्ट

उपस्थित:- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता अपीलांट।



निर्णय

दिनांक:-22.07.2024

अपीलांट धर्मपाल पुत्र हरद्वारीलाल जाति जाट निवासी मोड़ा खेड़ा तहसील आदमपुर जिला हिसार हरियाणा द्वारा विरुद्ध निर्णय दिनांक 01.10.2011 प्रकरण संख्या 21/2021 जिसकी रूह से वसीयत पत्रावली निरस्त की गई, को अपास्त किये जाने एवं मुताबिक वसीयत के अनुसार नामान्तरण दर्ज करने के आदेश दिये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है-

1. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 21/2021 दिनांक 01.10.2021 को विधि विरुद्ध एवं गैर कानूनी ढंग से निर्णय पारित किया गया है, जो अपास्तनीय है। प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय दिनांक 01.10.2021 सलग्न अपील मिमो है।

2. रोही मौजा भादरा के चक 3 ए.एम.एस. के खाता सं. 13/11 के मुरब्बा नम्बर 50, 51 में योग खाता की कुल 10 कित्ता की 2.0610 हैक्टेयर बाराणी महीना रास्ता व खाला की संयुक्त खाते की भूमि में से 1/3 हिस्सा रणजीत पुत्र देवीलाल जाति जाट साकिन चक 1 टी. सुलतान वाला तहसील पीलबंगा जिला हनुमानगढ़ के नाम दर्ज थी तथा उन्होने अपने जीवनकाल में अपने सगे भान्जा की सेवा से

प्रसन्न होकर खरीद शुदा कृषि भूमि थी, वसीयत धर्मपाल, नरेन्द्र, पि. हरद्वारीलाल जाति जाट साकिन गोड़ा खेड़ा तहसील आदमपुर जिला हिसार के पक्ष में करवा दी तथा उपरोक्त वसीयत दिनांक 09.05.2018 को छानीबड़ी सब रजिस्ट्रार भादरा से पंजीबद्ध है। फोटो प्रति वसीयतनामा सलग्न अपील मीमो है।

3. अपीलान्त व तरतीबी रेस्पो. सं. 2 के मामा की दिनांक 10.12.2020 को मृत्यु हो चुकी है तथा उनकी फौतदगी के बाद अपीलान्त ने मुताबिक वसीयत के अनुसार नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु तहसीलदार राजस्व भादरा के यहा प्रार्थना पत्र पेश किया तथा वसीयत की पत्रावली मुर्तिब की जाकर वसीयत में वर्णित भूमि की पटवारी हल्का की रिपोर्ट ली गई तथा गवाहों के बयान लिये गये तथा पत्रावली दिनांक 01.10.2021 को पेशी में ली जाकर वसीयत की पत्रावली का रेस्पो. सं. 1 द्वारा अवलोकन किया जाकर वसीयत पत्रावली निरस्त कर दी गई। रेस्पो. सं. 1 द्वारा पारित निर्णय कतई विधि विरुद्ध एक विधि की अवहेलना में पारित किया गया है, जो कि अपास्तनीय है।

4. वसीयत में वर्णित कृषि भूमि अपीलान्त एवं तरतीबी रेस्पो. के मामा रणजीत द्वारा खरीद शुदा भूमि थी एवं उपरोक्त वसीयत माननीय सब रजिस्ट्रार छानी बड़ी तहसील भादरा द्वारा रजि. थी एवं वसीयत में वर्णित भूमि पर किसी प्रकार विवाद या स्थगन आदेश नहीं था, जो कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट था तथा वसीयत में वर्णित कृषि भूमि खरीदशुदा कृषि भूमि थी तथा उसके वाबजुद की रेस्पो. सं. 1 द्वारा वसीयत की पत्रावली निरस्त किया जाना कतई गैर कानूनी है एवं रेस्पो. सं. 1 द्वारा पारित निर्णय विधि विरुद्ध होने से अपास्तनीय है।

5. वसीयत दिनांक 09.06.2018 की पत्रावली रेस्पो. सं. 1 द्वारा राजस्थान उप निवेशन अधिनियम 1955 की शर्तों सं. 28 (6) के हवाला देते हुए कि अन्तरित को आवंटन का अधिकारी होने के कारण अन्तरण किया जा सकता है। राजस्थान उपनिवेशन (भाखड़ा विक्रय नियम) रूल 1955 के नियम 13 (2) के अनुसार राजस्थान के बाहर के व्यक्ति को आवंटन नहीं किया जा सकता है तथा इसी आधार पर वसीयत विधि के अनुसार भारत में स्थिति किसी भी चल व अचल सम्पत्ति की वसीयत किसी भी भारतीय नागरिक के पक्ष में कि जा सकती है तथा वसीयत के आधार पर सम्पत्ति का कोई आवंटन नहीं होना था। रेस्पो. सं. 1 द्वारा गलत तथ्यों को आधार मानकर वसीयत की पत्रावली निरस्त की गई है, जो अपास्तनीय है।

6. अपीलाधीन निर्णय का अपीलान्त को ज्ञान नहीं था क्योंकि अपीलान्त को कानूनी पंचदगियों को कतई ज्ञान नहीं रहा है। अपीलान्त निर्णय की कोई सूचना नहीं होने कारण अपीलान्त को ज्ञान नहीं रहा तथा अपीलान्त ने दिनांक 04.01.2022 को



प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील प्रस्तुत कर रहा है तथा द्वितीय देरी में क्षमा करने का कारण रिटोरियस है तथा उस केस मियाद के बिन्दु पर खारीज योग्य नहीं है तथा फिर भी दफा 5 मियाद प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से अपील मिमो के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है।

7. अपील अपीलान्त न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार की है तथा ज्ञान से अन्दर मियाद है तथा उचित न्याय शुल्क पर तहरीर कर पेश है।

अतः अपील अपीलान्त प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.10.2021 निरस्त फरमाया जावे एवं मुताबिक वसीयत के अनुसार नामान्तरण दर्ज करने के आदेश रेस्पों. सं. 1 को फरमाये जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट संख्या -1 के नोटिस बाद तामिल प्राप्त। अधिवक्ता अपीलांत द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या-02 को तर्क किया गया। रेस्पोंडेन्ट संख्या-01 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भादरा से अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांत की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांत ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1955 की शर्तों सं. 28 (6) के हवाला देते हुए कि अन्तरित को आवंटन का अधिकारी होने के कारण अन्तरण किया जा सकता है। राजस्थान उपनिवेशन (भाखड़ा विक्रय नियम) रूल 1955 के नियम 13 (2) के अनुसार राजस्थान के बाहर के व्यक्ति को आवंटन नहीं किया जा सकता है। वसीयत विधि के अनुसार किसी भी चल व अचल सम्पत्ति की वसीयत किसी भी भारतीय नागरिक के पक्ष में कि जा सकती है तथा वसीयत के आधार पर सम्पत्ति का कोई आवंटन नहीं होना था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत तथ्यों को आधार मानकर वसीयत की पत्रावली निरस्त की गई है, जो अपास्तनीय है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 01.10.2021 को अपास्त कर अपील अपीलांत स्वीकार फरमाई जावे।

अधिवक्ता अपीलांत की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली का अध्ययन किया गया तो पाया कि वसीयत में वर्णित भूमि वसीयतकर्ता रणजीत पुत्र देवीलाल जाति जाट साकिन चक 1 टी. सुलतानवाला तहसील पीलीबंगा की खरीदशुदा है। यह तथ्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजस्व भादरा द्वारा दिनांक 01.10.2021 को पारित निर्णय में अंकित किया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा "राजस्थान उपनिवेशन(सामान्य कॉलोनी) शर्त 1955 की शर्त संख्या 28(6) के अनुसार इस अधिनियम के नियमों के अनुसार अन्तरित को आवंटन का अधिकारी होने पर ही अन्तरण किया जा सकता है एवं राजस्थान



उपनिवेशन(भाखड़ा विक्रय नियम) रूल्स 1955 के नियम 13(2) के अनुसार राजस्थान के बाहर के व्यक्ति का आवंटन नहीं किया जा सकता है" के आधार पर अपीलांट का वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने का प्रार्थना-पत्र खारिज किया गया है, जो कि न्यायोचित नहीं है क्योंकि अपीलांट द्वारा मुताबिक वसीयत नामान्तरण दर्ज करने का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया न कि भूमि आवंटन बाबत।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 39(5) के अनुसार- "एक व्यक्ति अपनी सम्पत्ति की वसीयत किसी व्यक्ति के पक्ष में कर सकता है, जो उसकी इच्छाओं के अनुसार उस सम्पत्ति को धारण करने योग्य है। विल करने के लिए धर्म कोई प्रतिबंध नहीं या बाधा नहीं है। एक "विल" (क) बच्चों और वारिसों (ख) अजन्में व्यक्ति (ग) धार्मिक या मूर्त संस्थानों के पक्ष में की जा सकती है।" अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजस्व भादरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.10.2021 में भूल कारित की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.10.2021 को अपास्त किया जाकर पत्रावली तहसीलदार भादरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) की जाती है कि नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा वसीयत पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फ़ैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ़तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवया जाकर आज दिनांक 22.7.24 को सरेइजलास सुनाया गया



(गोपाल लाल स्वर्णकार आर.एस.)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बोहर (सुमानगढ़)